भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या **916**

उत्तर देने की तारीख 04.12.2025

जनजाति-बहुल क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना

916. डॉ. इन्द्रा हांग सुब्बा:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास जनजाति-बहुल क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना प्रदान करने की योजनाएं हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार एनईईटी परीक्षा के लिए कोचिंग का लाभ उठाने हेतु आदिवासी छात्रों को किसी योजना या छात्रवृत्ति के माध्यम से सहायता प्रदान करती है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र के ऐसे जिलों की राज्य-वार संख्या कितनी है जिनमें एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय कार्यरत हैं; और

(घ) सिक्किम राज्य के उन जिलों की संख्या कितनी है जो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों से वंचित हैं तथा तत्संबंधी प्रासंगिक ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क) डिजिटल शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए ईएमआरएस में स्मार्ट क्लासरूम प्रदान किए गए हैं। वर्तमान में ईएमआरएस में 262 स्मार्ट क्लास रूम उपलब्ध कराए गए हैं।

(ख) एनईएसटीएस, जेईई/एनईईटी की तैयारी के लिए तीन उत्कृष्टता केंद्रों के माध्यम से एनेबल (सक्षम) कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन मोड और ऑफ़लाइन कोचिंग के माध्यम से सभी विज्ञान संकाय (स्ट्रीम) के छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान कर रहा है।

(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र में, कार्यात्मक ईएमआरएस का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य	कार्यात्मक ईएमआरएस की संख्या
1	अरुणाचल प्रदेश	5
2	असम	6
3	मणिपुर	5
4	मेघालय	2
5	मिजोरम	11
6	नागालैंड	3
7	सिक्किम	4
8	त्रिपुरा	12
	कुल	48

(घ) सिक्किम के चार जिलों अर्थात् ग्याल्शिंग, मंगम, नामची और पक्योंग में से प्रत्येक में एक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) स्वीकृत और कार्यात्मक है।

****